बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 213 ● नई दिल्ली ● बुधवार 10 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में अगले दो घंटे में बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर सहित हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले दो घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हल्की गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम और मानेसर में बारिश की संभावना है। हरियाणा के हिसार, हांसी, सिवानी, महम, तोशाम, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी में भी बारिश हो सकती है। मतानहेल, झज्जर, फर्रुखनगर, कोसली, रेवाड़ी और नूंह भी प्रभावित होंगे। राजस्थान के भिवाड़ी और खैरथल में भी मौसम बदलेगा।

15 लाख लोगों को राहत की उम्मीद, 92 कॉलोनियों को ओ-जोन से हटाने की मांग पर एलजी से मिले बीजेपी सांसद

नई दिल्ली। दिल्ली के 92 कॉलोनियों और दर्जनों प्राचीन गांवों को ओ-जोन से बाहर करने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मंगलवार (9 जून) को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु से मुलाकात कर इस मुद्दे पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया. सांसदों का दावा है कि वर्षों से लंबित इस मामले के कारण करीब 15 लाख लोग अनिश्चितता और कार्रवाई के डर के बीच जीवन गुजार रहे हैं. उपराज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में सांसदों ने कहा कि संबंधित गांवों और कॉलोनियों को 24 मार्च 2008 को नियमित किया जा चुका था. उस समय ये इलाके F Zone के अंतर्गत आते थे. लेकिन अगस्त 2010 में इन्हें यमुना के ओ-जोन में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ. सांसदों के अनुसार, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 28 सितंबर 2013 को इन क्षेत्रों को ओ-जोन से हटाने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था.

हालांकि, एक NGO की याचिका के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. बीजेपी सांसदों ने कहा कि जिस याचिका के आधार पर रोक लगी थी, उसका निपटारा जनवरी 2015 में हो चुका है. इसके बावजूद गांवों और कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर करने का अंतिम निर्णय अब तक नहीं लिया गया. इससे लाखों लोगों में असमंजस और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. मुलाकात के दौरान सांसदों ने उपराज्यपाल को बताया कि पूर्व उपराज्यपाल भी इन क्षेत्रों को ओ-जोन में शामिल किए जाने के फैसले को गलत बता चुके हैं. इसके अलावा DDA के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने भी माना था कि गांवों की आबादी का भूमि उपयोग आवासीय श्रेणी का है. इसके बावजूद कई इलाकों में तोड़फोड़ और कार्रवाई की शिकायतें सामने आती रही हैं.

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित कॉलोनियां यमुना नदी से काफी दूर स्थित हैं. वहीं केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति भी यह निष्कर्ष दे चुकी है कि इन बस्तियों से न तो यमुना के बहाव पर असर पड़ता है और न ही नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है. मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल से मांग की कि 2013 में जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लागू कर इन गांवों और कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर किया जाए. उनका कहना है कि ऐसा होने पर करीब 15 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो सकेगा.

संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी,अरविंद केजरीवाल बोले- पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बना रही ईडी

नई दिल्ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और राय सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय के यहां छापेमारी के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले में दावा किया कि पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है. आप के संयोजक ने कहा- ईडी पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है. ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है. उन्होंने लिखा कि मेरी सभी व्यापारियों से अपील है - घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे. आप संयोजक के बयान को रिपोस्ट करते हुए पंजाब से सीएम भगवंत मान ने भी प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा- पंजाब के हिंदू व्यापारी हमारे राय के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं और रंगला पंजाब बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है. ईडी पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके हमारे व्यापारियों को परेशान करना चाहती है. ऐसा करके वे राजनीतिक दबाव डालकर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पंजाबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम अपने व्यापारियों के साथ खड़े हैं. बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोबाइल फोन की बिक्री से संबंधित कथित 100 करोड़ रुपये के जीएसटी घोखाधड़ी के सिलसिले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को नए सिरे से छापेमारी की कार्रवाई की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के जालंधर और लुधियाना तथा उत्तर प्रदेश के बरेली और नोएडा में लगभग छह परिसरों पर छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिस परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उनमें अरोड़ा से जुड़ी कंपनी 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के मामले में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित आवास और व्यावसायिक कार्यालय दोनों शामिल हैं. अरोड़ा (62) को पिछले महीने चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर दिनभर की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अरोड़ा पंजाब में विद्युत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे. अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था.

पकड़ा गया मंत्रालय के ट्रेनिंग अफसर का झूठ, फर्जी एक्सपीरियंस लेटर से हासिल की नौकरी; कोर्ट में खुली पोल

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी गौरव मलिक को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित ने जिस कंपनी में वर्ष 1993 से कार्य करने का दावा किया था, उस कंपनी का गठन ही वर्ष 1995 में हुआ था। ऐसे में अनुभव प्रमाणपत्र में किया गया दावा सही नहीं पाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने अपने फैसले में गौरव मलिक को धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज के इस्तेमाल और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने जालसाजी की धारा के आरोप से उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपित ने प्रशिक्षण अधिकारी (व्यावसायिक सेवाएं) पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी, भोपाल का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। प्रमाणपत्र में दर्शाया गया था कि वह 10 मार्च 1993 से कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यरत था। इसी अनुभव के आधार पर उसका चयन हुआ और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। यूपीएससी के तत्कालीन उप सचिव ने गवाही में बताया कि उम्मीदवारों के आवेदन की छंटनी के बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उसी प्रक्रिया में गौरव मलिक का चयन हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी के साझेदार राकेश अग्रवाल ने अदालत में गवाही देते हुए कहा कि गौरव मलिक कभी उनकी कंपनी का कर्मचारी नहीं रहा। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। अदालत ने माना कि जब कंपनी का अस्तित्व ही वर्ष 1995 से पहले नहीं था तो वर्ष 1993 से उसमें नौकरी करने का दावा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया मूल अनुभव प्रमाणपत्र आरोपित के कब्जे में था। जांच एजेंसी द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद वह मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि आरोपित की ओर से दस्तावेज उपलब्ध न कराया जाना उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में सामने आता है। फैसले में अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपित ने अनुभव प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर नौकरी प्राप्त की और बाद में उससे जुड़े साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। मामले में दोषसिद्धि के बाद अब अदालत सजा के बिंदु पर आरोपित की दलीलें सुनेगी। वर्ष 1998 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के बाद यूपीएससी ने जनवरी 2000 में गौरव मलिक के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद जनवरी 2001 में उसे प्रशिक्षण अधिकारी पद पर नियुक्ति मिल गई थी।

लुटियंस दिल्ली में पोलो ग्राउंड खाली कराने के नोटिस पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दिल्ली का दम घुट जाएगा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की बची-खुची हरियाली को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर इसी तरह खुले और हरे-भरे क्षेत्रों को खत्म किया गया तो दिल्ली का दम घुट जाएगा. मामला लुटियंस दिल्ली स्थित ऐतिहासिक इंडियन पोलो एसोसिएशन के मैदान और अन्य प्रमुख संपत्तियों को केंद्र सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने से जुड़ा है. सरकार ने दावा किया है कि इन जमीनों की जरूरत रक्षा ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों के लिए है.

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने राजधानी में लगातार घटते हरित क्षेत्रों पर गंभीर चिंता जताई. अदालत ने कहा कि दिल्ली पहले ही प्रदूषण और भीड़भाड़ की मार झेल रही है और अब एनडीएमसी इलाके में बची हुई थोड़ी-बहुत खुली जगह भी खत्म की जा रही है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा दिल्ली का दम घुट जाएगा. अगर आप इसी तरह दिल्ली को चलाना चाहते हैं तो भगवान ही हम सबकी रक्षा करे. हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सरकार इस इलाके में ऊंची-ऊंची इमारतें बनाने की योजना बना रही है. अदालत ने कहा एनडीएमसी क्षेत्र में लोगों को सांस लेने के लिए जो थोड़ी खुली जगह मिलती है, वह भी खत्म होती जा रही है. ऐसे में हम सभी का दम घुटने लगेगा.

134 साल पुरानी संस्था को खाली करने का नोटिस

इंडियन पोलो एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1892 में हुई थी उसको हाल ही में बेदखली का नोटिस मिला है. यह मैदान प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित है. इसके खिलाफ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह बेदखली नोटिस पर रोक लगाने की मांग पर जल्द फैसला करे. इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है. दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि जमीन की आवश्यकता सार्वजनिक हित, प्रशासनिक कार्यों और रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल दिल्ली में मौजूद जमीन सीमित हैलेकिन सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन भी इसी क्षेत्र से करना पड़ता है.

जिम खाना क्लब को लेकर भी मामला पहुंचा था कोर्ट

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को लेकर भी ऐसा ही विवाद सामने आया था. सरकार ने वहां की जमीन को भी सार्वजनिक और प्रशासनिक जरूरतों के लिए जरूरी बताया था. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने IPA की याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को बेदखली नोटिस पर रोक लगाने की मांग पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के जीके-1 एन्क्लेव में इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग

नई दिल्ली। दिल्ली के जीके-1 एन्क्लेव में एक इमारत की चौथी मंजिल पर मंगलवार को आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। डीएफएस के अनुसार, पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एसी में आग लगने की सूचना के बाद शुरू में

दमकल की दो गाड़ियों को मौके भेजा गया और बाद में दमकल की छह और गाड़ियां व एक बहुउद्देश्यीय वाहन भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि आग मुख्य रूप से चौथी मंजिल में घरेलू सामान में लगी थी। उन्होंने बताया कि घटना से जुड़े अन्य विस्तृत विवरण की अभी प्रतीक्षा है।

समय बदल गया है, शादी से पहले सेक्स चरित्र आंकने का आधार नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। क्या दो अविवाहित बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए किया जा सकता है? क्या बिना शादी के खत्म होने वाले रिश्ते को अपने आप में एक धोखा माना जा सकता है? इन दोनों गंभीर सवालों का जवाब देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर नहीं में दिया है। सरकारी भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो कानून, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में दूरगामी असर डालेगा। ऐसे समय में जब शादी से पहले के रिश्तों को समाज में अब भी रूढ़िवादी नजरिए से देखा जाता है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्पष्ट किया है कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को किसी के चरित्र को आंकने का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सिर्फ इसलिए गलत काम का अनुमान लगाने की प्रवृत्ति के खिलाफ भी चेतावनी दी कि कोई रिश्ता आखिरकार टूट गया। जस्टिस मनमोहन और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को उस रिश्ते में शामिल व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत राय बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता और न ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिगों को अपनी पसंद का रिश्ता बनाने से रोकता हो। यह जानकारी बार एंड बेंच ने दी है। ये बातें तब सामने आईं जब कोर्ट तेलंगाना के पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती उम्मीदवार गजूला थिरुपति के मामले की सुनवाई कर रहा था। उनका चयन इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि एक दशक से भी पहले एक पड़ोसी के साथ रिश्ते से जुड़े एक आपराधिक मामले के कारण उन पर आरोप लगे थे। लेकिन यह फैसला सिर्फ यह तय करने से कहीं आगे का था कि क्या कोई उम्मीदवार सरकारी नौकरी का हकदार है या नहीं। बेंच ने एक ऐसे सवाल पर गौर किया जो कानून, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच अक्सर उठता है- क्या बालिगों को आपसी सहमति से बने उन रिश्तों के लिए सजा दी जानी चाहिए जो शादी में नहीं बदलते? कोर्ट ने संकेत दिया कि इसका जवाब नहीं है। फैसले में कहा गया, हर रिश्ता शादी में नहीं बदलता। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता शादी में नहीं बदला, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया है। यह बात बार एंड बेंच ने बताई है। कोर्ट ने माना कि सामाजिक सचाई बदल गई है और लोगों के आचरण का आकलन करते समय अधिकारी इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेंच के अनुसार, शादी से पहले के रिश्ते आज के समाज की सचाई हैं और संस्थानों को पुरानी सोच पर आधारित कठोर धारणाओं पर निर्भर रहने के बजाय बदलते समय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस फ़ैसले के सबसे अहम हिस्सों में से एक में जजों ने कहा कि जब दो बालिग़ लोग काफ़ी समय तक रिश्ते में रहते हैं, तो यह माना जाता है कि वह रिश्ता आपसी सहमति से बना था। बेंच ने कहा, इसके अलावा, जब ऐसा रिश्ता काफ़ी समय तक चलता है, जैसे कि कुछ साल, तो इस कोर्ट ने बार-बार उन आपराधिक मामलों को रद्द किया है जो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ख़िलाफ़ इस शिकायत पर शुरू किए थे कि पीड़ित को शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहलाया-फुसलाया गया था।

कूटनीति की ओर बढ़ते संबंध

भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से अत्यंत गहरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क और साझा सभ्यतागत विरासत ने रिश्तों को विशेष स्वरूप दिया है। हालांकि, समय-समय पर कुछ विवाद भी सामने आते रहे हैं, जिनमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र से जुड़ा सीमा विवाद सबसे प्रमुख है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नई दिल्ली में इस विवाद पर नेपाल की स्थिति स्पष्ट करते हुए, कहा कि काठमांडू किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता, बल्कि अपने ऐतिहासिक दावे को स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की खोज कर रहा है। यह बयान भारत-नेपाल संबंधों के वर्तमान स्वरूप और नेपाल की नई राजनीतिक दिशा को समझने का अवसर प्रदान करता है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का विवाद कई दशकों पुराना है। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि (1816) के अनुसार काली नदी के पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। नेपाल का कहना है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इसी आधार पर उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दूसरी ओर भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है और प्रशासनिक नियंत्रण भी भारत के पास है। यह विवाद विशेष रूप से तब उभरकर सामने आया जब भारत ने वर्ष 2020 में लिपुलेख तक सड़क निर्माण किया और नेपाल ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र में इस क्षेत्र को शामिल कर लिया। वर्ष 2026 में विवाद एक बार फिर चर्चा में आया जब भारत ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने की घोषणा की। भारत ने बताया कि यात्रा चीन के सहयोग से लिपुलेख और नाथुला मार्गों से संचालित होगी। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को राजनयिक नोट भेजा। नेपाल का तर्क है कि लिपुलेख उसके दावे वाले क्षेत्र में आता है और इसलिए वहां किसी भी गतिविधि में उसकी सहमति आवश्यक है। हालांकि, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने अपने हालिया वक्तव्य में यह स्पष्ट किया कि नेपाल तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से संपर्क का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त करना है, क्योंकि यह विवाद ब्रिटिश शासन के समय की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लगातार यह कहता रहा है कि सीमा विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होना चाहिए और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू नेपाल की बदलती राजनीति है। हाल के चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह के नेतृत्व का उदय नेपाल की राजनीति में बड़े परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। यह नेतृत्व स्वयं को पारंपरिक राजनीतिक दलों जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और माओवादी दलों से अलग बताता है। विदेश मंत्री खनाल ने कहा कि वे पूरी तरह नई राजनीतिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सुशासन, योग्यता आधारित व्यवस्था और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। दनई नेपाली सरकार का दावा है कि वह भारत को बीसवीं सदी की भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं के चश्मे से नहीं देखना चाहती। इसके बजाय वह डेवलपमेंट डिप्लोमेसी यानी विकास आधारित कूटनीति पर जोर देना चाहती है। इसका अर्थ है कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों को अपनी जगह रखते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना विकास को प्राथमिकता दी जाए। इसी दिशा में विदेश मंत्री खनाल और भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की हालिया बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों ने सीमा पार डिजिटल भुगतान प्रणाली के संचालन की घोषणा की। नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के नागरिकों और व्यापारियों को डिजिटल लेन-देन में सुविधा मिलेगी। यह कदम भारत-नेपाल आर्थिक संबंधों को नई गति दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की नई सरकार घरेलू मोर्चे पर अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है। प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह को हालिया चुनावों में मजबूत जनादेश मिला है और जनता उनसे त्वरित परिणामों की अपेक्षा कर रही है। यही कारण है कि सरकार फिलहाल घरेलू सुधारों और सुशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। विदेश मंत्री ने भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री शाह फिलहाल आंतरिक चुनौतियों पर केंद्रित हैं और इसलिए उनकी भारत यात्रा की कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। दभारत के लिए भी नेपाल अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच नेपाल का सामरिक महत्व और बढ़ गया है। भारत और नेपाल के बीच रक्षा, जल संसाधन, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के आवागमन से जुड़े अनेक साझा हित हैं। इसलिए दोनों देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को संवाद के माध्यम से सुलझाएं और व्यापक संबंधों को प्रभावित न होने दें। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट का है। यह समूह दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा और सुधार के लिए गठित किया गया था। हालांकि इसकी रिपोर्ट कई वर्षों से सार्वजनिक नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री खनाल ने कहा कि यह रिपोर्ट दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को सौंपी जानी है और इसके भविष्य पर अंतिम निर्णय वही करेंगे। यदि यह रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो संभव है कि भारत-नेपाल संबंधों को नई दिशा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। निष्कर्षतः, नेपाल-भारत संबंध वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं। एक ओर कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा विवाद जैसी पुरानी चुनौतियाँ मौजूद हैं, तो दूसरी ओर डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और विकास कूटनीति जैसे नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। नेपाल की नई राजनीतिक नेतृत्व पीढ़ी अतीत की कटुताओं से आगे बढ़ने की बात कर रही है, जबकि भारत भी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों की परिपक्व कूटनीति यह तय करेगी कि सीमा विवादों के बावजूद वे अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं।

पुतिन ने कई सारी गांठें खोल दी हैं !

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी कुछ बोलते हैं तो यह मान कर चलिए कि उसके पीछे कोई न कोई लक्ष्य होता है। पिछले सप्ताह जब सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने ग्लोबल न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों से बात की तो उनका लक्ष्य बड़ा साफ था। वे भारत के साथ रिश्तों का जिक्र करके न केवल अमेरिका बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी संदेश दे रहे थे कि रूस इस पुराने रिश्ते की मिठास कम नहीं होने देगा। भारत के लिए यह निश्चय ही भरोसे वाली बात है। यह पहली बार नहीं है जब रूसी राष्ट्रपति ने भारत से अच्छे संबंधों की दुहाई दी है। वे हर मौके पर भारत की तारीफ करते रहे हैं और सबसे भरोसे का पार्टनर भी बताते रहे हैं। और यह सच भी है, मगर इस बार चर्चा में उन्होंने 1947 का जिक्र किया जब सोवियत संघ ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने कहा कि तब से हम एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना में हरसंभव सहयोग करते रहे हैं। यह भारत को याद दिलाना भी हो सकता है और भरोसा दिलाना भी हो सकता है कि वो हम ही हैं जो हमेशा साथ खड़े हैं। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि अमेरिका या पश्चिमी देशों ने भारत के साथ क्या रिश्ते रखे लेकिन यह जरूर कहा कि रूस के साथ रिश्तों की गर्माहट को कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की जो कोशिशें हो रही हैं उससे हमारे रिश्ते प्रभावित नहीं होने वाले हैं। हमारे रिश्तों की दिशा नहीं बदलेगी। अब गौर कीजिए कि पुतिन ने यह सब क्यों कहा? इसके पीछे दो कारण नजर आते हैं। पहला तो यह कि इसी साल 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए पुतिन भारत आने वाले हैं। ध्यान रखिए कि इस साल पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा और दूसरा कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने ही वाला है।

पुतिन को पता है कि अमेरिका यह जरूर चाहेगा कि समझौता इस तरह का हो कि उसमें रूस को किसी न किसी रूप में घाटा हो और निश्चित रूप से पुतिन की चाहत होगी कि भारत हमेशा ही रूस का साथी बना रहे। वह अमेरिका के साथ रिश्ते भले ही अच्छे करे लेकिन रूस से दूर न जाए। यही कारण है कि जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका और भारत के बीच सहयोग, रूस और भारत के बीच रिश्ते में मुश्किलों का कारण बन रहा है, तो पुतिन का जवाब कुछ ऐसा था- आपकी बात मुझे अजीब लग रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें खुशी है कि भारत सभी देशों के साथ संबंध विकसित कर रहा है। यह एक महान देश है। 1.5 अरब लोगों का देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। स्वाभाविक है कि अपने हितों के अनुरूप वह उन देशों से संबंध विकसित करता है, जिन्हें वो जरूरी समझता है। इससे रूस कैसे प्रभावित हो सकता है? पुतिन की ये साफगोई बताती है कि भारत-रूस संबंधों को वे हर हाल में अपने पाले में रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि भारत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। दोस्ती से साथ जरूर रखा जा सकता है, इसीलिए वे नरेंद्र मोदी के साथ ही भारत के लोगों की तारीफ करना नहीं भूलते। वे जानते हैं कि भारत में रूस को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही गहरे रिश्ते रहे हैं। मैं खुद भी कई बार रूस गया हूं और रिश्ते की इस गर्माहट को मैंने महसूस किया है। दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का पुराना इतिहास है और पुतिन इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हाल के वर्षों में यह सवाल भी हमेशा पूछा जाता रहा है कि रूस और चीन करीब हो चुके हैं। पाकिस्तान के रिश्ते चीन के साथ बहुत मधुर हैं तो क्या इससे भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होंगे? पुतिन ने इसका भी जवाब अपने तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों की जटिलताओं को हम अच्छी तरह समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है, अभी तो पुतिन की बात गले नहीं उतरती क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के साथ ही चीन की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा है लेकिन पुतिन कह रहे हैं तो कुछ न कुछ राजनीति जरूर होगी। पुतिन एक पत्थर से कई फल तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। मगर ये भी सच है कि रूस के लिए भारत भी बड़े काम का देश रहा है। यूक्रेन के साथ संघर्ष के दौरान रूस को जब अलग-थलग करने की कोशिशें लगातार हो रही थीं तब भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों में कोई दरार नहीं आने दी और रियायती दरों पर रूस से तेल की खरीद जारी रही। अमेरिका तो इस बात से इतना नाराज भी हुआ था कि रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया था। बाद में इसे न केवल हटा लिया, बल्कि ईरान जंग के बाद रूसी तेल खरीद को लेकर छूट भी बढ़ाई गई। पुतिन को पता है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है अभी रूस के साथ व्यापार करीब 67 अरब डॉलर के आसपास है जिसे पुतिन 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। रूस ने भारत को सुखोई-57 फाइटर जेट तकनीक पर साथ काम करने का प्रस्ताव भी दिया है मगर भारत ने कहा कि आप विकसित कीजिए। संभव है कि हम बाद में इसमें शामिल हों, यानी पुतिन ने भारत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के हर रास्ते को सुगम करने की कोशिश की है। यह भारत के लिए भी निश्चय ही अच्छी बात है। हमें भी रूस के साथ दोस्ती का झूला झूलते रहना चाहिए। हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे।

इस अविश्वसनीय दुनिया में कोई तो भरोसे का साथी होना ही चाहिए।

सम्पादकीय...

पत्रकारिता और महिलाएं

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हुए, जिसका जश्न अनेक जगहों पर खूब मनाया गया। 30 मई, 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसके सम्पादक जुगल किशोर शुक्ल जी थे, लेकिन यह मात्र 18 महीने ही चल पाया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी किताब हिंदी पत्रकारिता में हिंदी के पुराने अखबारों और उनमें चलते बहस-मुबाहिसों का विस्तार से वर्णन किया है। इन 200 सालों में हिंदी ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हिंदी के लगभग 1000 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनकी प्रसार संख्या करोड़ों में है। सबसे अधिक समाचार पत्र उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नम्बर है। आर.एन.आई. के आंकड़ों के अनुसार, हिंदी के कुल पत्र-पत्रिकाओं की संख्या साढ़े चार हजार है। हिंदी को गति देने और उसे दुनिया की तीसरे नम्बर की भाषा बनाने में इन अखबारों, रेडियो, टी.वी. और फिल्मों का बड़ा हाथ है। एक समय में हिंदी अखबारों, पत्रिकाओं में महिलाओं की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक थी लेकिन आज हर तरफ वे ही दिखाई देती हैं। हिंदी की पहली महिला पत्रकार हेमंत कुमारी देवी को माना जाता है, जिन्होंने 1888 में लखनऊ से 'सुगृहिणी' नाम से पत्रिका निकाली थी। हेमंत कुमारी हिंदी भाषी न होकर बांग्ला भाषी थीं लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को महत्व दिया। तब से अब तक अगर मुहावरे में कहूं, तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है। करीब 49 साल पहले जब इस क्षेत्र में आई तो इस बड़े और स्थापित संस्थान में मात्र 5 महिला पत्रकार थीं, जिनमें से 2 दैनिक पत्र में, बाकी 3 दो पत्रिकाओं में। दूरदर्शन पर जरूर प्रतिमा पुरी, मुक्ता श्रीवास्तव, सलमा आदि दिखाई देती थीं। लेकिन 90 के दशक में भूमंडलीकरण के कारण जब मीडिया का फैलाव हुआ, अखबारों के अनेक संस्करण शुरू हुए, चैनल्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई, तो महिला पत्रकारों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसका बड़ा कारण महिलाओं में बढ़ती शिक्षा, आत्मनिर्भरता की भावना, कुछ अलग कर दिखाने की चाहत, साथ ही मीडिया का ग्लैमर भी। यही वह दौर था जब शीला झुनझुनवाला एक साप्ताहिक पत्र की सम्पादक बनीं। बाद में मृणाल पांडे भी इसकी सम्पादक बनीं। कुछ साल बाद वह इसी संस्थान के दैनिक पत्र के सभी संस्करणों की सम्पादक बनीं। वह पहली महिला पत्रकार थीं, जो किसी दैनिक की सम्पादक बनी थीं। दिल्ली एन.सी.आर. की हिंदी महिला पत्रकारों के योगदान पर पत्रकार वंदना अग्रवाल ने शोध भी किया है। 90 के दशक में महिला पत्रकारों की संख्या इस तरह से बढ़ रही थी कि उन्हें लगा कि अपने लिए एक अलग से क्लब होना चाहिए। इसलिए वुमन प्रैस कोर की स्थापना की गई। आज इस क्लब में हिंदी, अंग्रेजी दोनों को मिलाकर 1000 से अधिक पत्रकार सदस्याएं हैं। आज तो हालत यह है कि चैनल्स के प्राइम टाइम पर महिलाएं ही छाई हुई हैं। वे बड़े-बड़ों के छक्के छुड़ा देती हैं। उनकी विजिबिलिटी या दृश्यमानता चारों ओर बढ़ी है, तो उनका महत्व भी बढ़ा है। यही नहीं, महिला मुद्दों पर भी इनकी सक्रियता देखते ही बनती है। चाहे वह मथुरा रेप कांड हो, जिसमें मथुरा नाम की लड़की से पुलिस वालों ने ही दुष्कर्म किया था, दिवराला में 1987 में हुई सती और शाहबानो का मामला, निर्भया का मामला हो या फिर अन्य मामले। राजनीतिक विषयों से लेकर फिल्म, मनोरंजन, अपराध हर मामले में वे रिपोर्टिंग करती, लिखती नजर आती हैं।

विपक्षी एकता का अन्तर्विरोध

दिक्कत यह है कि कांग्रेस को मजबूरी में उनसे समझौता करना पड़ता है और राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर उन्हें अपनी नीतियों व विचारधारा का आवरण देना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जमीन पर इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के विरूद्ध संघर्ष करते हुए ही अपना जनाधार बनाया है। इस अर्थ में इंडिया गठबन्धन को मजबूरी का सौदा भी कहा जा सकता है परन्तु व्यावहारिक राजनीति में ऐसे सौदे नहीं चलते हैं। हमने देखा है कि किस तरह पूर्व में भी ऐसे गठबन्धन असफल रहे हैं। क्योंकि भारत की जनता जानती है कि इतने विशाल देश में केन्द्र के स्तर पर राजनैतिक स्थायित्व का रहना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि 1998 से लेकर 2014 तक केन्द्र में गठबन्धन सरकारों का दौर क्रमशः स्व. अटल बिहारी वाजपेयी व डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रहा मगर इसकी वजह सत्ता का आकर्षण ही रहा जिसके चलते लोकसभा के भीतर विभिन्न दलों ने केवल सत्ता के लिए विचारधारा को ताक पर रख कर गठबन्धन बनाये वरना क्या कभी सोचा जा सकता था कि जम्मू-कश्मीर की नेशनल कान्फ्रेंस व भाजपा एक ही सरकार में शामिल होंगी? मगर वाजपेयी शासन के दौरान यह हुआ और दक्षिण की द्रमुक पार्टी व ममता दी की तृणमूल कांग्रेस भी उनकी सरकार में शामिल रही। इसी प्रकार डा. मनमोहन सिंह की सरकार में भी कई वैचारिक रूप से धुर विरोधी पार्टियां शामिल रहीं। अतः चुनावों से पहले गठबन्धनों व चुनावों के बाद गठबन्धनों में आधारभूत अन्तर आ जाता है।

, देश के विपक्षी दलों में एकता के मुद्दे पर विचार-विमर्श उस समय चल रहा है जब प. बंगाल की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा सुश्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी में सुलगे विद्रोह से निपटने की असफल कोशिश कर रही हैं और इसके समानान्तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विरूद्ध अपने तीव्र मतभेदों को हवा देकर कांग्रेस के नेताओं के रवैये के विरूद्ध अपना मत जगजाहिर करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई है। इसके साथ ही दक्षिण की द्रमुक पार्टी व उत्तर की आम आदमी पार्टी ने गठबन्धन में शामिल न रहने की घोषणा कर दी है। दरअसल विपक्षी दलों के 2023 में बने 'इंडिया गठबन्धन' की हकीकत यह है कि यह ऐसी बेमेल विचारधाराओं और मत भिन्नताओं का जमावड़ा बन कर रह गया है जिसमें हर पार्टी के अपने निजी हित सर्वोच्च रहते हैं।

इसकी असली वजह विभिन्न क्षेत्रीय दलों का वह संकीर्ण नजरिया है जो उन्हें अपने राज्यों की सीमित राजनीति से बाहर निकलने ही नहीं देता है। ये सभी दल मिलकर अभी तक सत्ताधारी भाजपा के हिन्दुत्व परक राष्ट्रवाद के विमर्श के विकल्प के रूप में कोई ऐसा विमर्श प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर एकजुट होकर एक इकाई के रूप में भाजपा का मुकाबला करने की सर्वग्राह्य क्षमता हो। अभी हाल में जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबन्धन में इतनी भी कूवत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठा तक होकर भाजपा को ललकार सकें। इन राज्यों में प. बंगाल में जब ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो गई और चुनाव परिणाम आने के तुरन्त बाद जब इसके विजयी 80 विधायकों में से 60 ने खुला विद्रोह करके खुद को विधानसभा में असली विरोधी दल का दर्जा पा लिया तो ममता दी को सूझा कि अब उन्हें इंडिया गठबन्धन की शरण में जाना चाहिए जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी व मार्क्सवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने भी ममता दी पर भाजपा के साथ भीतरखाने सांठगांठ तक होने के आरोप लगाने तक में कोताही नहीं बरती थी। यही स्थिति दूसरे चुनावी राज्य केरल में भी थी जहां इंडिया गठबन्धन की सदस्य मार्क्सवादी पार्टी व कांग्रेस में जमकर युद्ध हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान श्री राहुल गांधी ने राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी के मुख्यमन्त्री श्री पिनरायी विजयन को बुरी तरह घेरते हुए आरोप लगाये थे कि उनके और प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच समझौता है तभी तो उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। श्री गांधी ने यहां तक आरोप लगाया कि मार्क्सवादी पार्टी व भाजपा के बीच अन्दरखाने समझौता हो चुका है। जाहिर है कि चुनावों के दौरान इंडिया गठबन्धन के घटक दलों के नेता जब आपस में इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगा सकते हैं तो भाजपा को उनपर हमला करने की क्या जरूरत? यह अन्तर्विरोध इतना गहरा है कि इसे चुनावी राजनीति की मजबूरी कह कर दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक- दूसरे पर अविश्वास का भाव बहुत गहरा है। मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव श्री एम. ए. बेबी ने तो कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक से पहले ही एक पत्र लिख कर साफ कर दिया कि कांग्रेस के इस प्रकार के रवैये को उनकी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने अपने पत्र की प्रतिलिपि गठबन्धन के हर घटक दल के नेता को भी भेजी और साफ कर दिया कि गठबन्धन का मतलब आपसी विश्वास से होता है। इसके साथ ही झारखंड के घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुख्यमन्त्री श्री हेमन्त सोरेन की शिकायत है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके राज्य से अपना राज्यसभा प्रत्याशी घोषित करने से पहले कोई मन्त्रणा ही नहीं की और इकतरफा तरीके से श्री प्रणव झा का नाम घोषित कर दिया। राज्य से दो सदस्यों का चुनाव होना है और सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस भी शामिल है। श्री सोरेन चाहते थे कि दोनों सीटें उनकी पार्टी ही लड़े मगर कांग्रेस ने उनसे सलाह किये बिना ही प्रणव झा को प्रत्याशी बना दिया। ये ऐसे मसले हैं जिनका स्थायी हल निकले बिना इंडिया गठबन्धन की एकता व मजबूती की गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनैतिक धरातल पर विचारों के क्षेत्र में शून्यता लिये रहते हैं। इनकी कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती और लोकसभा चुनावों में उन्हें देश की समस्याओं से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के हितों को साधने की वैकल्पिक नीति जैसे मुद्दों से जूझना पड़ता है अतः वे कांग्रेस के साथ आकर अपना बचाव करते हैं और बदले में कांग्रेस से अपने-अपने राज्यों में अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं। दिक्कत यह है कि कांग्रेस को मजबूरी में उनसे समझौता करना पड़ता है और राष्ट्रीय राजनैतिक फलक पर उन्हें अपनी नीतियों व विचारधारा का आवरण देना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जमीन पर इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के विरूद्ध संघर्ष करते हुए ही अपना जनाधार बनाया है। इस अर्थ में इंडिया गठबन्धन को मजबूरी का सौदा भी कहा जा सकता है परन्तु व्यावहारिक राजनीति में ऐसे सौदे नहीं चलते हैं। हमने देखा है कि किस तरह पूर्व में भी ऐसे गठबन्धन असफल रहे हैं। क्योंकि भारत की जनता जानती है कि इतने विशाल देश में केन्द्र के स्तर पर राजनैतिक स्थायित्व का रहना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि 1998 से लेकर 2014 तक केन्द्र में गठबन्धन सरकारों का दौर क्रमशः स्व. अटल बिहारी वाजपेयी व डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रहा मगर इसकी वजह सत्ता का आकर्षण ही रहा जिसके चलते लोकसभा के भीतर विभिन्न दलों ने केवल सत्ता के लिए विचारधारा को ताक पर रख कर गठबन्धन बनाये वरना क्या कभी सोचा जा सकता था कि जम्मू-कश्मीर की नेशनल कान्फ्रेंस व भाजपा एक ही सरकार में शामिल होंगी? मगर वाजपेयी शासन के दौरान यह हुआ और दक्षिण की द्रमुक पार्टी व ममता दी की तृणमूल कांग्रेस भी उनकी सरकार में शामिल रही। इसी प्रकार डा. मनमोहन सिंह की सरकार में भी कई वैचारिक रूप से धुर विरोधी पार्टियां शामिल रहीं। अतः चुनावों से पहले गठबन्धनों व चुनावों के बाद गठबन्धनों में आधारभूत अन्तर आ जाता है। इंडिया गठबन्धन में जिस प्रकार की धुर विरोधी पार्टियां शामिल हैं उनमें आपसी हितों का टकराव चुनावों में जाते समय तो रहेगा ही अतः ये दल अगर सीट समझौता करके चुनाव लड़ें तो वह अधिक व्यावहारिक होगा। यह बेशक कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना एक शर्त होती है मगर यह शर्त तो विपक्ष को ही पूरी करनी होगी। आज की बैठक में 25 दलों में केवल 5 मुद्दों पर सहमति होने से एकीकृत विपक्ष नहीं बनता।

इंसानी गलतियों का बोझ उठाती धरती

भारत में गर्मी के रूप में आसमान से आफत बरस रही है। तापमान की त्यौरियां लगातार चढ़ रही हैं और सूरज आग बरसा रहा है। पिछले दो-तीन दशकों से मौसम विज्ञानी चेतावनी देते आ रहे हैं लेकिन वैश्विक तापक्रम वृद्धि को रोकने के लिए सरकारों और आम जनमानस ने कोई खास ध्यान नहीं दिया है। कई देशों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इन हालात का असर न सिर्फ इंसानों की सेहत पर पड़ रहा है बल्कि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिरकार मौसम का मिजाज लगातार गर्म क्यों हो रहा है? वास्तव में हर साल रिकॉर्ड तोड़ती भीषण गर्मी और असंतुलित होता मौसम सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर मंडराता हुआ एक बड़ा खतरा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से धरती का तापमान जिस तेजी से बढ़ा है, उसने प्रकृति के पूरे चक्र को बिगाड़ कर रख दिया है। पानी के स्रोतों का सूखना, ग्लेशियरों का पिघलना और मिट्टी की नमी का खत्म होना इस बात का साफ संकेत है कि पृथ्वी का प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम अब दम तोड़ रहा है। ऐसे में यह सवाल बेहद गंभीर हो जाता है कि आखिर इंसानी गलतियों के कारण हमारी धरती कब तक जीवन का बोझ उठा पाएगी। औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्टों के मुताबिक, औद्योगिक काल की तुलना में धरती का औसत तापमान पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का यह आंकड़ा 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, तो पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा जिससे जीवन को वापस पटरी पर लाना नामुमकिन हो जाएगा। 1901 से 1930 के मुकाबले इस सदी के पिछले दशक 2015 से 2024 में भारतीय भू-भाग का औसत तापमान लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। तापमान में यह बढ़ोतरी एक जैसी नहीं रही है। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में पिछले तीन दशकों के दौरान तापमान में हर दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां एक ओर भारतीय क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी, मौजूदा वैश्विक तापमान वृद्धि के स्तर लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले कम है, वहीं भारत में तापमान की चरम स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत के अधिकतर हिस्सों में गर्म दिनों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। गर्म दिन की संख्या में हर दशक 5 से 10 दिनों तक की बढ़ोतरी हुई है। गर्म दिन परिभाषा के मुताबिक, उन दिनों को कहा जाता है जब अधिकतम तापमान 1995-2014 की अवधि के दौरान के दैनिक अधिकतम तापमान के 90वें परसेंटाइल से अधिक होता है बीती गई दिन का तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, और जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। दुनिया भर के सबसे गर्म 100 शहरों में ज्यादातर भारत के हैं। यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। आज से साढ़े पांच सौ वर्ष पूर्व, श्री गुरु नानक देव जी ने पवन गुरु, पाणि पिता, माता धरती महातु का संदेश देकर प्रकृति के इन उपहारों से प्रेम करने, उनका सम्मान करने और उन्हें संरक्षित करने पर जोर दिया था, लेकिन आम लोग और अमीर लोग मनोरंजन, फैशन, बातचीत, पर्यटन और मौज-मस्ती के लिए धरती माता की गोद से निकलने वाले पैट्रोलियम उत्पादों, बिजली, पानी, धातुओं, रसायनों और परमाणु ऊर्जा जैसे अनगिनत बहुमूल्य संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोग मनोरंजन और पर्यटन के लिए पहाड़ों और धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लाखों लीटर पैट्रोल, तेल, प्लास्टिक और धन का उपभोग करके पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। भोजन, पानी और हवा को संरक्षित करने के बजाय, वे लगातार नष्ट हो रहे हैं। दोपहिया वाहन एक या दो लोगों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन वाहनों में केवल एक ही व्यक्ति को यात्रा करते देखा जाता है। साइकिल और पैदल चलना लगभग बंद हो गया है। लेकिन 90 प्रतिशत लोग पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। दुनिया के कुछ रेगिस्तानी देशों का तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो सामान्य सहनीय तापमान से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बढ़ते तापमान, गर्मी और उमस को कम करने के बजाय, उन्होंने और भारतीयों ने एसी का उपयोग बढ़ा दिया। हर घर, संस्थान, इमारत, वाहन, कारखाने, होटल, मैरिज पैलेस, सिनेमा हॉल, छत्ते में एसी लगा दिए गए, जो दिन-रात ऑक्सीजन और नमी को नष्ट कर रहे हैं

और गर्मी बढ़ा रहे हैं। गर्मी बढ़ने का सबसे पहला और सीधा प्रहार पृथ्वी के जल चक्र (वाटर साइकिल) पर हो रहा है। कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण बारिश का पानी जमीन के भीतर नहीं जा पा रहा है, जिससे भूजल (ग्राउंडवाटर) का रिचार्ज पूरी तरह रुक गया है। नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, भारत सहित दुनिया के कई बड़े शहरों में ग्राउंडवाटर का स्तर शून्य के करीब पहुंच रहा है। यदि पानी का यह प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया, तो अगले कुछ दशकों में ही पीने के पानी का भयंकर अकाल पड़ जाएगा। धरती के बढ़ते तापमान का सबसे बड़ा और खतरनाक असर हमारे मीठे पानी के मुख्य स्रोतों यानी ग्लेशियरों पर देखने को मिल रहा है। हिमालय और ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर रिकॉर्ड रफ्तार से पिघल रहे हैं, जिससे शुरुआत में तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है, लेकिन इसका दूसरा और डरावना पहलू यह है कि एक बार जब ये ग्लेशियर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो गंगा, यमुना जैसी सदानीरा नदियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा जिससे करोड़ों लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। इस गर्मी का सीधा असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। कई राज्यों के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी और लू लगने के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर मजदूरों, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फारेनहाइट माना जाता है। थर्मामीटर पर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस और 95 से 108 डिग्री फारेनहाइट के निशान होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि मनुष्यों, बच्चों और बुजुर्गों का तापमान बहुत कम हो जाता है, तो रक्त संचार और रक्तचाप में कमी के कारण हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, यकृत आदि अंगों में रक्त की आपूर्ति बहुत कम हो सकती है, जिससे दिल का दौरा, हृदय गति रुकना, बेहोशी और कोमा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मस्तिष्क को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पानी की आपूर्ति बंद होने से मस्तिष्क निष्क्रिय हो सकता है। सांस रुक सकती है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों और कंप्यूटर मॉडलों के अनुसार, यदि इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन को तुरंत नियंत्रित नहीं किया, तो अगले 100 से 200 सालों के भीतर पृथ्वी के कई हिस्से इंसानी आबादी के रहने लायक नहीं बचेंगे। अत्यधिक हीटवेव के कारण इंसानी शरीर का तापमान झेलने की क्षमता जवाब दे जाएगी। हालांकि, पृथ्वी से जीवन पूरी तरह खत्म होने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन इंसानी सभ्यता और बड़े जीवों का अस्तित्व महज कुछ सदियों में ही भीषण गर्मी, सूखे और भुखमरी के कारण पूरी तरह समाप्त हो सकता है।

यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो वैश्विक तापमान में 2050 तक लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2100 तक 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। विज्ञान स्पष्ट है कि यदि उत्सर्जन में भारी कमी की जाए, तो तापमान वृद्धि धीमी हो सकती है और अंततः स्थिर हो सकती है। हम अभी तापमान को पूरी तरह से कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे और बढ़ने से रोक सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पँचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा- दो दिनों में 20,921 अभ्यर्थी अनुपस्थित

पहले दिन 10,691, दूसरे दिन 10,230 ने छोड़ी परीक्षा; प्रशासन सख्त, सुरक्षा चाक-चौबंद

गोरखपुर।

जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू होकर 10 जून तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं। बावजूद इसके, पहले दो दिनों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन कुल 38,928 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 28,237 ही उपस्थित हुए, जबकि 10,691 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में 19,464 में से 14,037 उपस्थित और 5,427 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में 14,200 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 5,264 गैरहाजिर रहे। दूसरे दिन भी अनुपस्थिति का सिलसिला जारी रहा। प्रथम पाली में 19,464 में से

14,316 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 5,148 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में19464 में से 14,382 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 5,082 ने परीक्षा नहीं दी। इस तरह दूसरे दिन कुल 10,230 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दो दिनों की चार पालियों को मिलाकर कुल 20,921 अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है, जो एक बड़ी संख्या है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि जनपद में इस परीक्षा के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 19,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तीन दिनों में कुल 6 पालियों के माध्यम से 1,16,784 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने का कार्यक्रम निर्धारित है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है। प्रवेश के दौरान सघन जांच, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। डीआईजी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीएम सिटी और एसपी सिटी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ कराई जा रही है। पहले दो दिन परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, और शेष पालियों के लिए भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

गोरखपुर की कोच रीता मिश्रा ने नाम किया रोशन

• 9वीं सीनियर नेशनल इंदौर हॉकी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार खेल

गोरखपुर। गोरखपुर की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं कोच रीता मिश्रा ने एक बार फिर जनपद का नाम रोशन किया है। उनके कुशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में टीम ने 9वीं सीनियर नेशनल इंदौर हॉकी चैंपियनशिप 2026, बड़ौदा गुजरात में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतियोगिता में टीम ने गोवा के विरुद्ध 0-0 से मैच ड्रॉ खेला, जबकि तेलंगाना के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत दर्ज कर अपने दमदार प्रदर्शन का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने मैदान में अनुशासन, आत्मविश्वास, तालमेल और संघर्ष क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम की गोलकीपर मुशकान ने शानदार बचाव करते हुए विपक्षी टीमों के हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं फुल बैक पंक्ति में कोयलेता, अश्रीता टोपो, अनिता एक्का, योति शर्मा, पूनम पासवान और शकुंतला राव ने मजबूत रक्षण का परिचय दिया। फारवर्ड लाइन में प्रेमलता सिंह, रश्मि सिंह, पम्मी और फरजाना ने तेज और आक्रामक खेल दिखाते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया।

कोच रीता मिश्रा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने पूरे समर्पण, अनुशासन और एकजुटता के साथ खेला है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले मुकाबलों में भी खिलाड़ी इसी जोश और लगन के साथ बेहतर प्रदर्शन करेंगी। गोरखपुर की कोच रीता मिश्रा के नेतृत्व में टीम के इस शानदार प्रदर्शन से जिले के खेल जगत में खुशी की लहर है।

खेल प्रेमियों ने टीम और कोच रीता मिश्रा को आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

तहसील सभागार में लगी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को कप्तानगंज तहसील सभागार में विकास, सुशासन, सेवा एवं जनकल्याण विषयक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोड एवं मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान विधायक विनय प्रकाश गोड ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा एवं मजदूर वर्ग के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास के साथ-साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदर्शनी में तहसीलदार चंदन शर्मा, नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी, बीडीओ अमरनाथ पांडेय, चेयरमैन प्रतिनिधि विजय खेतन, राधेश्याम दीक्षित, सुपरवाइजर मनीष सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, जिला स्टेडियम में योग प्रशिक्षकों को कराया गया प्रोटोकॉल अभ्यास

कुशीनगर। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर जिला स्टेडियम कुशीनगर में योग प्रशिक्षकों के लिए विशेष अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास सत्र का संचालन मास्टर योग ट्रेनर अभय रंजन मिश्र द्वारा किया गया। उन्होंने योग वैलनेस सेंटर एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़े प्रशिक्षकों को योग दिवस प्रोटोकॉल का विस्तृत अभ्यास कराते हुए विभिन्न योग क्रियाओं के सही तरीके एवं उनके महत्व की जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. जगदीश यादव ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने प्रशिक्षकों से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक विशाल सिंह ने कहा कि योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 15 से 20 जून तक जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में प्रतिदिन योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षकों से अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर योग के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा नियमित योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र कुमार, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्र सहित अन्य अधिकारी एवं योग प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

खेत की खुदाई में निकले कथित मुगलकालीन चांदी के सिक्के, कुशीनगर के अझवलिया गांव में उमड़ी भीड़

कुशीनगर।

जनपद के तरयासुजान थाना क्षेत्र के अझवलिया गांव में खेत की खुदाई के दौरान कथित रूप से पुराने चांदी के सिक्के मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और पूरे इलाके में यह चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब चार बजे गांव के एक खेत में मिट्टी खनन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान जमीन के भीतर से कुछ पुराने

सिक्केनुमा धातु के टुकड़े मिलने की बात सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों का दावा है कि बरामद सिक्के काफी पुराने हैं तथा संभवतः मुगलकाल से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी विशेषज्ञ संस्था अथवा प्रशासन द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूचना मिलते ही तरयासुजान पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सिक्कों की संख्या, उनकी वास्तविकता तथा ऐतिहासिक महत्व के संबंध में जांच कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। उधर, कथित प्राचीन चांदी के सिक्के मिलने की खबर से आसपास के गांवों में भी उत्सुकता का माहौल है। ग्रामीणों के बीच सिक्कों की उत्पत्ति और उनके ऐतिहासिक महत्व को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद वस्तुएं वास्तव में ऐतिहासिक महत्व के सिक्के हैं या नहीं।

संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों ने शव रखकर किया सड़क जाम

कुशीनगर। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया स्थान बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा पडरौना-बांसी मुख्य मार्ग को करीब दो घंटे तक जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या कर शव को फेंका गया है, जबकि पुलिस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि काफी

समझाने-बुझाने और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद उग्र ग्रामीण सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से शव हटाकर गांव के संपर्क मार्ग पर रखकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

पीएम मोदी एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कैबिनेट फेरबदल और परिसीमन बिल पर बढ़ीं अटकलें

नई दिल्ली। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर होने जा रही एनडीए की बड़ी बैठक अब सिर्फ विकास योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट फेरबदल, भाजपा संगठन में बदलाव और परिसीमन बिल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत और काकोली घोष दस्तीदार के पलटवार ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में विकसित भारत विजन, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और राज्यों के साथ समन्वय पर चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी विस्तार से बातचीत होने की संभावना है। बढ़ती महंगाई, ईंधन और रसोई गैस की कीमतों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। बैठक में केंद्र और राज्यों के साझा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि एनडीए की बैठक के बाद केंद्र सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। जून 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी सरकार में अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा पुनर्नामांकन सूची से बाहर रखे जाने के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को बैठक खत्म होने के बाद भी दिल्ली में रुकने को कहा गया है। इससे माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन दोनों में बदलाव हो सकते हैं। भाजपा और एनडीए के भीतर परिसीमन बिल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार इस बिल को फिर से लाने की कोशिश कर सकती है। यह प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए परिसीमन और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा है। अप्रैल में यह बिल लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाया था। लेकिन अब छह अपनी संख्या बढ़ने को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद एनडीए के साथ आते हैं, तो सरकार को संसद में बड़ी ताकत मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस में जारी संकट अब राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता दिख रहा है। अगर टीएमसी के बागी सांसद एनडीए का समर्थन करते हैं, तो संसद में एनडीए की ताकत और बढ़ सकती है। इससे परिसीमन बिल जैसे बड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भाजपा पहले ही 12 साल पूरे होने पर देशभर में कार्यक्रम चला रही है और विपक्षी दलों की कमजोर होती स्थिति को अपने पक्ष में देख रही है।

पटाखा फैक्ट्री में आग, 2 भाइयों समेत 8 की मौत

जयपुर । जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में एक बच्चे, दो भाइयों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। पटाखा फैक्ट्री मकान नंबर- 88 करीम नगर-बी में रिहायशी इलाके में चल रही थी। मकान याकूब पुत्र नजीर खान निवासी- राख्या की ढाणी खोह नागोरियान का है। याकूब ने अपना मकान फिरोज निवासी- नई दिल्ली को किराए पर दे रखा है। फिरोज मकान में अवैध रूप से शादी के पटाखों की पैकिंग करवाता था। घटना के बाद से मकान मालिक और फैक्ट्री मालिक की तलाश की जा रही है।

इनकी हुई मौत

मरने वालों में मोहम्मद अशरफ (40) पुत्र मोहम्मद शकील निवासी- पीरजी कॉलोनी, मोहम्मद रब्बिल (16) पुत्र मोहम्मद सिकंदर निवासी- करीम नगर-2 तलाई, अब्दुल वहीद (46) पुत्र अब्दुल अजीज निवासी- रहीम नगर, समीर खान (20) पुत्र अनिस खान निवासी- रहीम नगर, बिलाल खान (28) पुत्र नासिर निवासी- रहीम नगर, आजीम खान (18) पुत्र नासिर खान निवासी- रहीम नगर, नासिर खान (25) पुत्र मोहम्मद अली निवासी- रहीम नगर खोह नागोरियान के रहने वाले थे। एक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। इनमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मरने वालों में दो सगे भाई

आजीम और बिलाल सगे भाई थे। बिलाल आज छोटे भाई आजीम की फैक्ट्री देखने गया था, जहां आजीम काम करता था। वहां बैठकर दोनों बातचीत कर रहे थे। इस दौरान लगी आग में दोनों झुलस गए थे।

पुलिस कमिश्नर बोले- दोषियों पर कार्रवाई होगी

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया- जहां हादसा हुआ, वो वहां पटाखा रखने का गोदाम था। फैक्ट्री कुछ दूर है। पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। रिहायशी इलाके में गोदाम अवैध रूप से था। इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसएसओ ओमप्रकाश ने बताया- फिरोज वसीम नाम के युवक के साथ मिलकर अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित कर रहा था।

आग शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से लगने की आशंका

पुलिस का कहना है कि बस्रु टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए गए हैं। जिसकी जांच के बाद ही फैक्ट्री में कितना विस्फोटक मौजूद था, उसका पता चल सकेगा। इसके साथ ही आग लगने के कारणों का भी जांच में ही पता लगेगा। शुरुआती जांच में आग शॉर्ट सर्किट या किसी के बिड़ी-सिगरेट जलाने की चिंगारी से लग सकती है।

ट्रंप ने माना ईरान ने मार गिराया अमेरिका का अपाचे हेलिकॉप्टर, बोले- सेना देगी जवाब

वॉशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने रात के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में गश्त कर रहे अमेरिका के एक अपाचे हेलिकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने इस घटना पर जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प भी जताया, हालांकि उन्होंने कोई अन्य जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे अभी-अभी हमारी सेना ने सूचित किया है कि बीती रात ईरानियों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर गश्त कर रहे हमारे अत्याधुनिक अपाचे हेलिकॉप्टरों में से एक को मार गिराया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी होगी।

हेलिकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें सेना ने जानकारी दी है कि ईरानी बलों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में अभियान के दौरान एक अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। उन्होंने यह भी कहा कि घटना में शामिल दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। ट्रंप ने लिखा, इसमें दो पायलट शामिल थे, दोनों सुरक्षित हैं और घायल नहीं हुए हैं। फिर भी, इस हमले का जवाब देना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवश्यक है। यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि मंगलवार तड़के स्थानीय समयानुसार करीब तीन बजे ओमान के तट के निकट क्षेत्रीय जलक्षेत्र में गश्त मिशन के दौरान एक एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

अमेरिकी सेना ने चलाया बचाव अभियान

सेना ने दुर्घटना के कारण की जानकारी नहीं दी और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, सैनिकों को लगभग दो घंटे के भीतर सुरक्षित बचा लिया गया और उनकी स्थिति स्थिर है। घटना के कारण की जांच की जा रही है। अमेरिकी सेना के इतिहास में पहली बार यह बचाव अभियान एक मानवरहित सतही पोत की मदद से अंजाम दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के कॉर्सेयर स्वायत्त सतही ड्रोन ने पानी में मौजूद दोनों चालक दल के सदस्यों का पता लगाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें एक अन्य स्थान तक पहुंचाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ऊपर उठाया गया। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता नौसेना कप्तान टिम हॉकिन्स ने कहा कि ड्रोन का चयन उसकी निकटता और परिचालन क्षमता को देखते हुए किया गया था।

कॉर्सेयर पोत का किया इस्तेमाल

कॉर्सेयर 24 फुट लंबा स्वायत्त पोत है, जो लंबी दूरी तक यात्रा करने और पर्याप्त भार वहन करने में सक्षम है। यह बचाव अभियान सैन्य अभियानों में मानवरहित प्रणालियों की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना को टास्क फोर्स 59 को समुद्री अभियानों में स्वायत्त तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

मानसून ने 13 राज्य कवर किए, आज मुंबई पहुंचेगा

नई दिल्ली । मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया है। सोमवार को तेलंगाना में एंट्री कर चुका है। फिलहाल यह मुंबई से करीब 150 किमी दूर है और अगले 48 घंटे में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं, अगले सप्ताह तक यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंच सकता है। मानसूनी हवाओं के असर से कई मैदानी राज्यों में गर्मी कम हुई है। साथ ही प्री-मानसून के कारण कई जगह 50-60किमी रफ्तार से आंधी और तेज बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को बेंगलुरु और बेलगावी में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगहों पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आईं। इधर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी का असर बना हुआ है। कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। सोमवार को श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 45.6°C दर्ज किया गया।

अखिलेश ने किया भाजपा के 225 विधायकों के टिकट कटने का दावा

जयपुर । जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में स्थित पटाखों के गोदाम में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई और 4 मजदूर झुलस गए। मरने वालों में रामगंज निवासी अब्दुल वाहिद शामिल है। तीन की शिनाख्त नहीं हुई है। झुलसे आजीम खान (18), नासिर खान (20), समीर खान (20) और बिलाल (22) को SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये खोह नागोरियान में रहीम नगर के रहने वाले हैं। एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आरके जैन ने बताया- समीर और नासिर 95त झुलस गए। बिलाल 75फीसदी और आदिब 65फीसदी जल गया। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया- पटाखों का गोदाम खोह नागोरियान में आयशा नगर तलाई क्षेत्र आईटीआई कॉलेज के पास है। कोई ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग लगी है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया- जहां हादसा हुआ, वो पटाखे रखने का गोदाम है। इसकी फैक्ट्री कुछ दूर है। पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। रिहायशी इलाके में गोदाम अवैध रूप से था। इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक अमीन कागजी ने कहा- रिहायशी इलाके में बारूद का गोदाम होने का क्या पुलिस को नहीं पता था। लोग भी किसके दबाव में हैं, जो बोल नहीं रहे हैं। यह किसका है, किसका नहीं, इस पर भी कोई जवाब नहीं है। विधायक ने कहा कि अब जिम्मेदार कहेंगे मरने वाले राजस्थान के नहीं हैं, तो क्या जीवन उनका नहीं है। फेल्योर तो आपका है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस करें पीएम, बताएं 12 साल में क्या किया- संजय राउत

मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और जनता को अपने 12 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दें। हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना को लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए संजय राउत ने कहा कि मौजूदा सरकार पंडित नेहरू के कार्यों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ जारी है, लेकिन इसके चलते लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। देश के चुनाव आयोग को भी कुचला जा रहा है।

वे कई संवैधानिक संस्थाओं के कंधों पर सवार होकर चल रहे हैं। इसलिए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का साहस दिखाना चाहिए। वैश्विक दबाव के कारण ही उन्हें ऑपरेशन सिंदूर को भी समाप्त करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। पंडित नेहरू एक प्रतिभाशाली नेता थे जो देश के स्वतंत्रता संग्राम से उभरे थे। पंडित नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर दी थी। आज उनकी संपत्ति का मूल्य 80 हजार करोड़ रुपये है। पंडित नेहरू ने सार्वजनिक उद्यम स्थापित किए। तेल कंपनियां, एलआईसी, आईआईटी और भी बहुत कुछ।

मोदी ने क्या किया? उन्हें आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताना चाहिए... आपने भले ही पंडित नेहरू के कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ा हो, लेकिन पंडित नेहरू के कार्यों के रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव नहीं है। इस बीच, नई दिल्ली में गठबंधन की बैठक के बाद जब राउत से पूछा गया कि इंडिया ब्लॉक के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी आम आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, जो वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए, ने गठबंधन में एकता का आह्वान किया। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे का फैसला नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट रहना चाहिए। अगर मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कोई भी आम आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। इंडिया ब्लॉक ने सोमवार को एक बैठक की, जिसमें 25 पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया।

संतोष हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लगी आग, बमुश्किल बची मरीजों की जान

मुरादनगर (गाजियाबाद) । गाजियाबाद के संतोष हॉस्पिटल की ओपीडी में मंगलवार की देर रात अचानक आग लग गई। इमरजेंसी में मौजूद चार मरीजों की बामुश्किल मुश्किल जान बचाई गई। मौके पर पहुंची सिहानी गेट पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने इमरजेंसी के शीशे तोड़कर सिलेंडर से निकली गैस को बाहर निकाला और फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर काबू पाया।

नाइट्रोजन के सिलेंडर लीक होने से लगी आग

सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि संतोष अस्पताल की इमरजेंसी पेंडेंट के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिलेंडर लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि गैस लीक होने से आग बढ़ती गई। इमरजेंसी में मौजूद चार मरीजों को ट्राईसिकल से बाहर निकाला गया। सूचना पर एसीपी नंदग्राम नियाउद्दीन अहमद और सिहानी गेट पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने इमरजेंसी के शीशे तोड़कर गैस को बाहर निकाला और इमरजेंसी खाली कराई। समय रहते प्रबंधन और पुलिस ने सिलेंडर से निकली गैस और आग पर काबू पा लिया। बताया कि दो गाड़ी मौके पर भेजी गई थी। हालांकि इससे पूर्व ही आग पर काबू पा लिया गया।

अस्पताल से बाहर भागे मरीज

आग लगने का सायरन बजते ही मरीज और तीमारदार जान बचाने जद्दोजहद में अस्पताल से बाहर निकल आये। तीमारदार अपने अपने मरीजों को लेकर सड़क और परिसर में पहुंचे। बागपत के गांव डालमपुर से आए चरण सिंह के परिजनों ने बताया कि उन्होंने गंभीर हालत में मंगलवार की शाम ही वृद्ध चरण सिंह को स्वास लेने की दिक्कत होने पर भर्ती कराया था। आग लगने की सूचना पर उन्हें इमरजेंसी से लेकर दौड़े।

हाइड्रेंट सिस्टम मिला खराब

सीएफओ ने बताया कि एजेंसी का हाइड्रेंट सिस्टम पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा था। सिस्टम के लॉक और पाइप में जंक लगा था। आग बढ़ जाती तो बड़ा हादसा होने की आशंका थी। अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा जाएगा। संतोष हॉस्पिटल की इमरजेंसी में देर शाम करीब 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी मरीजों को सकुशल बचा लिया गया है। इमरजेंसी के शीशे तोड़कर गैस को बाहर निकाला गया। फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर पुलिस ने ही काबू पा लिया था। दमकल विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है।

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक : कोर्ट में वकील बोले- गोली खान सर ने नहीं चलाई

पटना । फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है। इधर, खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

रायसभा चुनाव विवाद - नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस का बड़ा कदम, आज चुनाव आयोग से करेगी मुलाकात

भोपाल । मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज किए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को बैठक के लिए समय दिया है। एक अधिकारी के अनुसार, चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच यह बैठक 10 जून को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल ने कहा कि आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली में बातचीत के लिए समय देने का निर्णय लिया है।

आयोग ने कांग्रेस से यह भी पूछा है कि बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम उपलब्ध कराए जाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था।

कमलनाथ क्या बोले?

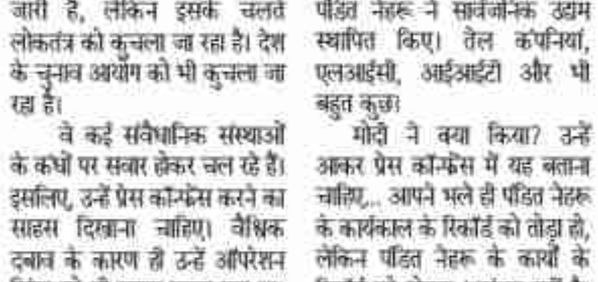

पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर अलोकतांत्रिक तरीकों से कांग्रेस को राज्यसभा सीट छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासनिक और प्रक्रियागत हथकंडों के जरिए कांग्रेस के चुनाव अभियान को प्रभावित करना चाहती है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पहले नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई और बाद में विधानसभा परिसर में हंगामा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है और भाजपा को इसका राजनीतिक जवाब मिलेगा।

भाजपा क्या बोली?

भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी छिपाई है। आपत्ति के अनुसार, पूर्व कॉर्पोरेट अधिकारी ए. श्रीलता ने हैदराबाद की अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि नटराजन ने कुंभम शिवकुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण दिया, जिन पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कांग्रेस नेता क्या बोले?

मीनाक्षी नटराजन ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया और कहा कि उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह याचिका दायर की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भाजपा के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की वसूली संबंधी कार्रवाई पर जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है। तन्खा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और न ही कोई आपराधिक मामला लंबित है।

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 10 जून को चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी का नामांकन खारिज किया जाना भाजपा की एक साजिश है। मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना में कांग्रेस मामलों की प्रभारी (एआईसीसी इंचार्ज) हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच x पर पोस्ट करते हुए कहा कि वोट चोरी और एसआईआर के बाद अब भाजपा सीट चोरी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में भाजपा की उस साजिश की निंदा करता हूं, जिसके कारण मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा नामांकन खारिज हुआ। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है और सभी नागरिकों को इसकी निंदा करनी चाहिए। हम सभी न्याय के लिए लड़ेंगे।

सीएम योगी ने पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर दी बधाई

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक विस्तृत पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जनभागीदारी को विकास की महत्वपूर्ण शक्ति में परिवर्तित किया है और सुशासन को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), पीएम गति शक्ति, डिजिटल परिवर्तन तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में योगदान दिया है। उन्होंने मिशन लाइफ, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता जैसी पहलों का भी उल्लेख किया और कहा कि इनसे विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों का प्रभाव गरीब कल्याण, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, स्वास्थ्य, तकनीकी नवाचार, रक्षा आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित कई क्षेत्रों में देखा गया है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान अवधि सेवा, सुशासन और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई भी दी। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद वह 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित हुए और 2024 के आम चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।